

भारत सरकार
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 2006
28.07.2014 को उत्तर दिए जाने के लिए

पंचायतों की स्वच्छता स्थिति

2006. डा. टी. एन. सीमा:

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में महज 12 प्रतिशत से थोड़ा अधिक हिस्से में ही पाइप वाली जल प्रणाली से जुड़े फलश युक्त शौचालय हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;
- (ग) क्या सरकार प्रत्येक पंचायत की स्वच्छता स्थिति का कोई मूल्यांकन अध्ययन कराने का विचार रखती है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार के पास गांवों में पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं के सृजन के लिए निजी माध्यम से धन प्राप्त करने की कोई योजना है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
राज्य मंत्री, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
(श्री उपेन्द्र कुशवाहा)

(क) 2011 की जनगणना के अनुसार, पाइप वाली सीवर प्रणाली में जोड़े गए फलशयुक्त शौचालय देश में 11.9% परिवारों में हैं।

(ख) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-1 पर है। भारत सरकार, खुले में शौच करने की प्रथा का उन्मूलन करने तथा स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम, निर्मल भारत अभियान (एनबीए) का, जो कि एक व्यापक कार्यक्रम है, पूरे देश में संचालन करती है। एनबीए का उद्देश्य सम्पूर्ण समुदायों में एक चरणबद्ध तरीके से संतृप्तिबोध

मोड में स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का प्रावधान करके सतत् व्यवहारगत परिवर्तन लाकर, 'निर्मल ग्राम' की स्थिति को परिणाम रूप में प्राप्त करना है। निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत त्वरित स्वच्छता कवरेज के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (बीपीएल) के अतिरिक्त वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के निर्माण के लिए प्रोत्साहनों का प्रावधान, पहचाने गए गरीबी रेखा से ऊपर के (एपीएल) परिवारों (सभी अनुसूचित जाति/जनजाति, छोटे और सुविधाहीन किसानों, अधिवास वाले भूमिहीन मजदूरों, शारीरिक रूप से विकलांग और महिला आश्रित परिवारों) तक बढ़ाया गया है।
- निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण के लिए सभी पात्र लाभार्थियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, 3200/- रुपए की पूर्ववर्ती राशि को बढ़ाकर 4600/- रुपए कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त शौचालय के निर्माण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत 5400/- रुपए तक का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 900/- रुपए के लाभार्थी अंशदान के साथ ही शौचालय की कुल इकाई लागत अब 10,900/- रुपए (पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 11,400/-रुपए) है।
- सूचना, शिक्षा, संप्रेषण (आईईसी) संबंधी गतिविधियों के लिए जिला परियोजनाओं के कुल परिव्यय में से चिन्हित 15% की राशि के साथ आईईसी गतिविधियों पर अधिक बल दिया गया है।
- ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के साथ संयुक्त दृष्टिकोण को विकसित किया गया है।
- संबंधित मंत्रालयों जिसमें स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय शामिल हैं, के कार्यक्रमों के साथ-साथ ग्रामीण स्वच्छता (एनबीए) के तालमेल पर बल दिया गया है।
- मनरेगा (एमजीएनआरईजीएस) के साथ तालमेल करके ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन (एसएलडब्लूएम) के घटकों को परियोजना आधारित दृष्टिकोण में बदला गया है।

- स्वच्छता के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाना, 12वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय 37159 करोड़ रुपए पर निर्धारित किया गया है, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय के 6540 करोड़ रुपए से 468% अधिक है।

(ग) एवं (घ) भारत सरकार ने 2012 में सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से आधारभूत सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया था जो कि पंचायतों की स्वच्छता की स्थिति उपलब्ध कराएगा। 23.7.2014 की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय की ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, **29 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की 242136 ग्राम पंचायतों में आधारभूत सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है।** आधारभूत सर्वेक्षण में बताया गया है कि लगभग **40.27%** ग्रामीण परिवारों को सफाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-2 पर है।

(ड.) और (च) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की पर्याप्त सुविधाएँ जुटाने के लिए निजी वित्त-पोषण को प्रोत्साहित किया जाता है। पारिवारिक शौचालयों एवं समुदाय स्वच्छता परिसरों (सीएससी) के निर्माण एवं सीएससी के लिए तथा स्कूल शौचालयों के रख-रखाव के लिए वित्त-पोषण कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के कार्य-कलापों का एक भाग हो सकता है। मंत्रालय ने स्वच्छता के क्षेत्र में सीएसआर निधियों के निवेश को आसान बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन की गतिविधियों के लिए प्राइवेट पब्लिक भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाएं भी प्रारंभ की जा सकती हैं।

दिनांक 28.07.2014 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2006 के भाग (ख)
के उत्तर में उल्लिखित विवरण

2011 की जनगणना के अनुसार पाइपवाली सीवर प्रणाली में जोड़े गए फलश युक्त शौचालयों का
राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत

राज्य/संघराज्य क्षेत्र	परिवारों की संख्या	पाइप वाले सीवर में जोड़े गए फलश युक्त शौचालयों की संख्या	पाइप वाली सीवर प्रणाली में जोड़े गए फलश युक्त शौचालयों का प्रतिशत
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	93376	2414	2.6
आंध्र प्रदेश	21024534	2615637	12.4
अरुणाचल प्रदेश	261614	15600	6.0
असम	6367295	328701	5.2
बिहार	18940629	342578	1.8
चंडीगढ़	235061	201831	85.9
छत्तीसगढ़	5622850	140128	2.5
दादर और नगर हवेली	73063	3591	4.9
दमन एवं दीव	60381	3195	5.3
गोवा	322813	46640	14.4
गुजरात	12181718	3530818	29.0
हरियाणा	4717954	1034710	21.9
हिमाचल प्रदेश	1476581	109481	7.4
जम्मू एवं कश्मीर	2015088	200545	10.0
झारखण्ड	6181607	230929	3.7
कर्नाटक	13179911	2994610	22.7
केरल	7716370	922284	12.0
लक्षद्वीप	10703	253	2.4
मध्य प्रदेश	14967597	864102	5.8
महाराष्ट्र	23830580	4375612	18.4
मणिपुर	507152	30668	6.0
मेघालय	538299	31294	5.8
मिजोरम	221077	12595	5.7
नागालैंड	399965	13249	3.3
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली	3340538	1979839	59.3
ओडिसा	9661085	245165	2.5
पुदुचेरी	301276	42244	14.0
पंजाब	5409699	1531120	28.3
राजस्थान	12581303	904740	7.2
सिक्किम	128131	15094	11.8
तमिलनाडु	18493003	2656697	14.4
त्रिपुरा	842781	29768	3.5
उत्तर प्रदेश	32924266	2666270	8.1
उत्तराखण्ड	1997068	235405	11.8
पश्चिम बंगाल	20067299	1113584	5.5
	246692667	29471391	11.9

दिनांक 28.07.2014 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2006 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

आधारभूत सर्वेक्षण 2012 के अनुसार शौचालयों की सुविधा सहित ग्रामीण परिवारों का राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	शौचालयों की सुविधा सहित परिवारों का प्रतिशत
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	53.77
2	आंध्र प्रदेश	30.86
3	अरुणाचल प्रदेश	41.53
4	असम	42.09
5	बिहार	21.41
6	छत्तीसगढ़	39.57
7	गोवा	60.72
8	गुजरात	52.75
9	हरियाणा	75.10
10	हिमाचल प्रदेश	86.04
11	जम्मू एवं कश्मीर	24.47
12	झारखण्ड	28.02
13	कर्नाटक	35.41
14	केरल	94.68
15	मध्य प्रदेश	26.17
16	महाराष्ट्र	48.04
17	मणिपुर	51.28
18	मेघालय	52.23
19	मिजोरम	74.04
20	नागालैंड	49.78
21	ओडिसा	42.27
22	पंजाब	75.17
23	राजस्थान	27.29
24	सिक्किम	81.55
25	तमिलनाडु	44.79
26	त्रिपुरा	62.60
27	उत्तर प्रदेश	35.24
28	उत्तराखण्ड	67.14
29	पश्चिम बंगाल	55.31
कुल :-		40.27